Deccan Hearld - 15 March-2024

Future-proofing cities: Expert bats for efficient use of water

Groundwater extraction high, country dependent on rainfall

R KRISHNAKUMAR
BENGALURU, DHNS

Sustainability of groundwater sources needs to be at the centre of Bengaluru's development blueprint as the city grapples with the inevitability of unchecked growth and failed monsoons set off by climate change, water resource expert Dipankar Saha said.

The former member-secretary of the Central Ground Water Authority underscored water use efficiency as critical to the sustainable management of urban sprawls. Saha is currently a board member of the India division of Water For People, a US-headquartered non-profit that works on clean water solutions.

Bengaluru's ongoing water crisis is not a lot unlike the one faced by surface water-dependent cities like Mumbai or groundwater-dependent cities like Patna.

"The issue in Bengaluru is that the high rate of urbanisation – both vertically and through the annexing of peri-urban areas – leaves traditional water supply networks and surface water sources short. The pressure is immense on groundwater sources and management of these sources is inadequate," Saha told *DH*.

Calling source sustainability "a major challenge", he said climate change was aggravating the crisis as the rainfall patterns become increasingly unpredictable. "Since the groundwater extraction is too high, cities are becoming more and more dependent on rainfall. This is happening across urban India but the trend has spiked in Bengaluru," he said.

Saha has led the National Aquifer Mapping and Management Programme as National Coordinator.

DIPANKAR SAHA
Board Member, Water for People India

"The issue in Bengaluru is that the high rate of urbanisation – both vertically and through the annexing of peri-urban areas – leaves traditional water supply networks and surface water sources short. The pressure is immense on groundwater sources and management of these sources is inadequate.

Improving water use efficiency is one of the strategies adopted in the Atal Bhujal Yojana (Atal Jal), the union government's community-led groundwater management project. Atal Jal which covers water-stressed areas in Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, and Uttar Pradesh supports volumetric metering and real-time data systems and increasing awareness of groundwater governance.

"Supply-side interventions like rainwater harvesting and artificial recharging can have a limited impact in areas with acute overexploitation (of groundwater). There is a new emphasis on demand-side interventions, specifically on enhancing water use efficiency. A lot of work is being done in this connection in the irrigation sector which consumes about 90% of the groundwater but water use efficiency in the urban areas is less discussed," Saha said.

Pitching a decentralised, community-led approach to groundwater management, Saha said civic agencies also needed to work with domain experts to devise science-backed strategies that factor in contingencies like climate change. While treated greywater has immense potential to meet non-potable demands, its mainstreaming will need to involve stringent quality checks, he said.

Rajasthan Patrika - 15 March -2024

राजस्थान ने मध्यप्रदेश से मांगा पानी, गांधी सागर से छोड़ा

गर्मी से पहले प्रदेश के 342 बांध रीते, गहराया पेयजल संकट

कोटा और बांसवाड़ा के अलावा ज्यादातर जल स्रोत सूखने लगे

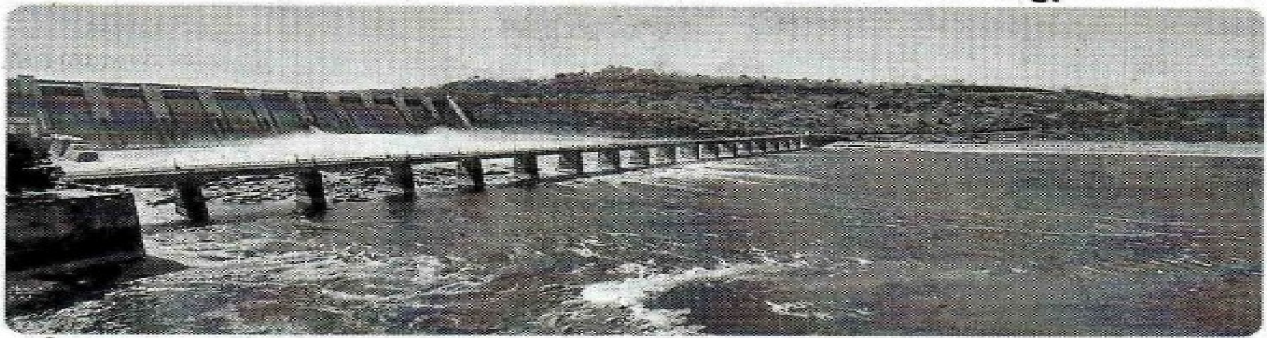

गांधी सागर का एक गेट खोलकर पानी छोड़ा गया।

रणजीतसिंह सोलंकी
patrika.com

कोटा. प्रदेश में मानसून की बेरुखी का असर इस बार गर्मी में देखने को मिलेगा। गर्मी शुरू होने से पहले ही प्रदेश के 342 बांध सूख गए हैं। 340 बांधों में भी आंशिक ही पानी बचा है। कोटा और बांसवाड़ा के अलावा प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर जल स्रोत मार्च आते-आते सूखने लग गए हैं। चम्बल नदी के दूसरे बड़े बांध राणा प्रताप सागर का ही पानी डेप्थ लेवल पर पहुंचने पर राजस्थान सरकार ने मध्यप्रदेश से गांधी सागर बांध से पानी मांगा है। इस पर दो दिन पहले गांधी सागर बांध से पानी छोड़कर राणा प्रताप बांध का जल स्तर बढ़ाया गया है।

जल संकट से निपटने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। पेयजल संकट वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर टैंकरों से जलापूर्ति की जाएगी। पानी के लिए राज्य सरकार से 50 लाख का बजट मिल चुका है।
- पीके बागला, अधीक्षण अभियंता, जलदाय विभाग कोटा

सरकार भी *अलर्ट मोड पर*

प्रदेश में संभावित जल संकट को लेकर सरकार भी अलर्ट मोड पर है। जल्द लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि पेयजल संकट को लेकर कोई आंदोलन खड़ा हो। सभी कलक्टरों को पेयजल संकट वाले संभावित क्षेत्रों को चिह्नित कर टैंकरों से जलापूर्ति के बंदोबस्त करने के लिए कहा है। खुद कलक्टरों को जलापूर्ति के संबंध में निगरानी रखने को कहा है। तालाब और बांध सूखने पर पशुओं के लिए जल संकट हो जाएगा। मारवाड़ से पशुपालक पलायन कर हाड़ौती की ओर रुख करने लग गए हैं।

संभागवार बांधों की जल भराव क्षमता

संभाग	कुल बांध	भराव क्षमता	उपलब्ध पानी
कोटा	80	4249.30	2497.15
जयपुर	252	2828.34	809.63
जोधपुर	116	970.96	252.57
बांसवाड़ा	59	2713.51	1515.10
उदयपुर	181	1902.32	642.17

जल भराव क्षमता एम क्यूएम में

(स्रोत : जल संसाधन विभाग के अनुसार)

मप्र से मांगा पानी

चम्बल नदी से हाड़ौती के अलावा भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा क्षेत्र में जलापूर्ति की जाती है।

चम्बल की नहरों में जल प्रवाह सुचारू रखने के लिए राजस्थान ने मध्यप्रदेश से गांधी सागर बांध से पानी मांगा। इस पर मध्यप्रदेश ने गांधी सागर बांध का एक गेट खोलकर 18 हजार क्यूसेक पानी दिया है।

इस बार चम्बल नदी का दूसरा सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप खाली रह गया था।

Rajasthan Patrika **- 15 March -2024**

नदी जल को शुद्ध कर पेयजल रूप में उपलब्ध कराने पर होगा काम: नीतीश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को यहां एक, अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में उनके समक्ष जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा खेल विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण बैठक में कहा कि जल एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर जल-जीवन-हरियाली अभियान चलाया गया है।

उन्होंने कहा कि भविष्य में जनसंख्या वृद्धि और भूगर्भ जल के स्तर में हो रही गिरावट को देखते हुए विभिन्न नदियों के अधिशेष जल का बरसात में भंडारण कर उसे शुद्ध पेयजल के रूप में उपलब्ध कराए जाने की योजना पर काम किया जाएगा। बैठक में इससे पूर्व जल संसाधन विभाग के तहत जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत अधिशेष नदी जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में ले जाने संबंधित योजना का प्रस्तुतीकरण दिया गया। विकास आयुक्त सह जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने पटना शहर के लिए पेयजल योजना के साथ-साथ औरंगाबाद, डिहरी, अरवल, सासाराम, जहानाबाद, भभुआ, मोहनिया एवं अधौरा पर्वत (कैमूर जिला) पर पेयजल उपलब्ध कराने की योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

गंगाजल आपूर्ति योजना में मिला शुद्ध पेयजल

मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगाजल आपूर्ति योजना के अंतर्गत राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा शहरों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इससे लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में जनसंख्या वृद्धि और भूगर्भ जल के स्तर में हो रही गिरावट को देखते हुए जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत विभिन्न नदियों के अधिशेष जल का बरसात माह में भंडारण कर उसे शुद्ध पेयजल के रूप में उपलब्ध कराए जाने की योजना पर काम किया जाएगा।